

झारखण्ड सरकार वारा काशत

वध (वधान) वभाग

का दजाभा ेदान करने हेतु और उससे संबं आनुषंगिक मामल के संदभा मं आवंयक है।

एतारा भारतीय गणराय के उहतरवष वषभा मं झारखण्ड विधान-सभा ँरा

निलिखत ँप मं

अधिनयमत ढकया जाता है:

ारंभिक

1. विंतर एवं ँरंभ:

- 1) यम, 2018 "कहा जाएगा।
- 2) इसका विंतर संपूणभा झारखण्ड राय मं होगा।
- 3) यह उस तिथि से ृत होगा जैसा ढक राय सरकार ँरा शासकय राजपू मं

अधिसूचना जारी कर नियत ढकया जाय।

2. पहरभाषा:-

अगर इस अधिनयम के संदभा मं अयथा अपेित/आवंयक हो:

(क) 'अकादिमक पहरषद्' का अथभा है विविंालय कऽ अकादिमक पहरषद् जैसा ढक अधिनयम कऽ

धारा-24 मं वणत है;

(ख) 'वाषक ृतवेदन' का आशय है विविंालय का वाषक ृतवेदन जैसा अधिनयम कऽ

धारा-39 मं संदभत है;

(ग) 'बंधन' बोडभा का अथभा है, इस अधिनयम कऽ धारा-23 के तहत गठत विविंालय का

बंधन बोडभा;

(घ) 'पहरसर' का आशय है विविंालय का ैफल जहाँ यह अविंथत है;

(ङ) 'कुलाधिपित' से आशय है विविंालय के कुलाधिपित, जो इस अधिनयम कऽ धारा-12

के अधीन नियु ह;

(च) 'मुद्रय विवृ एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विविर्विवालय के मुद्रय विवृ एवं लेखा

पदाधिकारी जो अधिनयम कऽ धारा-18 के अधीन नियुक्त हऽ;

(छ) 'परीक्षा नियंत्रक' का अर्थ है विविर्विवालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकऽ नियुक्ति

अधिनयम कऽ धारा-19 के अधीन हुई हो;

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अक्टूबर,2018

3

(ज) 'अंगीभूत महाविद्यालय' से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो

विविर्विवालय द्वारा संपोषित हऽ;

(झ) 'कर्मचारी' से आशय है विविर्विवालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अतःगणत विविर्विवालय

एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हऽ;

(ञ) 'स्थायी निधि' का अर्थ है विविर्विवालय कऽ स्थायी निधि जिसकऽ स्थापना अधिनयम कऽ

धारा-37 के तहत हुई हो;

(ट) 'संकाय' से आशय है समान अनुशासन के अकादमिक विभाग;

(ठ) 'शुद्ध' का आशय है विविर्विवालय द्वारा विवालय से उगाही गयी राशि, जो ठकसी

पाठम

तथा उससे संबंधित हो;

(ड) 'सामाज्य निधि' से आशय है विविर्विवालय कऽ सामाज्य निधि, जिसकऽ स्थापना अधिनयम

कऽ धारा-38 के अतःगणत हुई हो;

(ढ) 'शासी निकाय' का अर्थ है विविर्विवालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनयम कऽ

धारा-22 के तहत हुआ हो;

- (ण) 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रोत्सायन पद्धति' से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रोत्सायन पद्धति,
बहुमूल्य, विविधालय अनुदान आयोग का एक विभाग संस्था;
- (त) 'विविधत/नियत' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विविधत/नियत पद्धतिनियम और
नियमावली;
- (थ) 'उचित-कुलपित' का अर्थ है विविधालय के उचित कुलपित, जिनका नियुक्ति
अधिनियम का
धारा-15 के तहत शर्त हो;
- (द) 'कुलसिचव' का अर्थ है विविधालय के कुलसिचव, जिनका नियुक्ति अधिनियम का
धारा-17
के तहत शर्त हो;
- (ध) 'नियंत्री निकाय' का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर
के सुनिश्चित हेतु
मानक एवं शर्त के निधारण के लिए स्थापित निकाय, यथा-विविधालय अनुदान
आयोग, अखिल
भारतीय तकनीक शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पद्धति, भारतीय
विश्वविद्यालय पद्धति, बार
काउंसिल ऑफ इंडिया, फामसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं
प्रोत्सायन पद्धति,
भारतीय नक्षत्र पद्धति, भारतीय कृषि अनुसंधान पद्धति, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध
पद्धति
आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य
सरकार द्वारा
गठित किया गया हो;

(न) 'नियमावली' से आशय है इस अधिनियम के अतः गठित निम्नलिखित नियमावली;

झारखण्ड गजट (असाधारण) गु+वार, 11 अक्टूबर, 2018

(प) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;

(फ) विधिविवालय से संबंधित 'व्यवस्थापक निकाय' का अर्थ है:-

(i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अतः गठित कोई संस्था, अथवा

(ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक उपास, अथवा

(iii) किसी राज्य का विधि के अनुसूप पंजीकृत कोई संस्था या उपास।

(ब) 'राज्य सरकार' से आशय है झारखण्ड का राज्य सरकार;

(भ) 'पहरिनयम' 'अज्ञात' और 'विनियम' का अर्थ है, पहरिनयम, अज्ञात और

विनियम जो इस अधिनियम के अतः गठित विधिविवालय द्वारा निम्नलिखित ह;

(म) 'विधिविवालय के विवाह' का अर्थ है विधिविवालय में उपाधि, विद्वानों या अथवा विधिविवालय

द्वारा स्थापित अथवा अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम

नामांकित

वि

, जिसमें

शोध-उपाधि भी शामिल है;

(य) 'शिक्षक' से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर

अथवा इस तरह के अन्य

वि, निम्नलिखित नियुक्ति विधिविवालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था

में नियुक्ति करने

(विशेषण) अथवा शोधकायिका संचालन हेतु शई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय
अथवा संस्थान के

प्रधानाचार्यिका भी सम्मिलित ह., विजनक संयुक्त विद्यालय अनुदान आयोग

द्वारा विनियमनित नियम

के अंतर्गत शई हो;

(र) 'विद्यालय अनुदान आयोग' से आशय है विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,
1956 के अधीन स्थापित विद्यालय अनुदान आयोग;

(ल) 'विद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत झारखण्ड मंत्रि स्थापित
राधा

विद्यालय;

(व) 'कुलपित' से आशय है विद्यालय के कुलपित, विजनक नियुक्ति इस अधिनियम
क

धारा-13 के तहत शई हो;

(श) 'विजटर/अतिथि/आगतुक' से आशय है विद्यालय के
विजटर/अतिथि/आगतुक

यथा इस अधिनियम क धारा-10 मंत्रि वरुणत है।

3. विद्यालय क स्थापना

(1) गोविंद विद्यालय के नाम से होगी।

(2) विद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अंतर्गत होगा तथा यह रामगढ़
अवस्थित होगा।

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अक्टूबर,2018

5

(3) प्रवर्तक विनियम को राज्य सरकार द्वारा प्रधिकार

प्र जारी किये जाने के बाद ही विद्यालय का संचालन आरंभ किया
जायेगा।

(4) इस अधिनियम कऽ अनुसूची 'ए' मऽ सिमिलत शतऽ को

विजिविवालय निधाऽनरत समयाविध मऽ पूरा करेगा।

(5) विजिविवालय के शासी निकाय, ँबंधन बोडऽन, अकादिमक पऽरषद्,

कुलाधिपित, कुलपित, ँति कुलपित, कुलसिचव, िशिक, मुय विवृ एवं लेखा

पदाधिकारी एवं अय अधिकारी या सदंय या ँाधिकारी एतऽारा विजिविवालय के

नाम से गऽठत निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा उनकऽसदंयता बनी

रहेगी।

(6) विजिविवालय एक असऽबऽ विजिविवालय के ऽप मऽ कायऽन करऽगे और वे ऽकसी

भी महाविवालय या

संथान मऽ नामांककत विवाऽथयऽ को उपाधि (िडऽी), िडऽलोमा और ँमाण-

पऽ ँदान करने हेतु

सबऽता नहऽ दे सकऽगे।

(7) इस अधिनियम के ँभावी होने के पूवऽन ँवतऽनक निकाय के अंगीभूत

महाविवालय और संथान, जो सऽबऽता ँाऽ ह. और विजिविवालय के विवेषाधिकार

का उपयोग कर रहे ह. वे इस अधिनियम के ँभावी होने के साथ ही उस विजिविवालय

से असऽबऽ हो जाऽगे, उनकऽ ऐसी सुविधाऽँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समू

हो जाऽगी और राधा

निकाय ऽऽऽारा ँदऽ सुविधाऽ के साथ ऐसे महाविवालय और संथान उस

राधा गोविद विजिविवालय के अंगीभूत महाविवालय या संथान बन जाऽगे।

(8) गोविद विजिविवालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के

ँावधानऽ के अनुऽप

उसके पास सतत् पद-ःािर् अनुक्रम और सामाज्य ःतिीा ःमाणन कऽ शि

होगी, सपित ळहण करने

व उस पर आधपय रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा किथत नाम से वाद चलाने के

अधिकार हगे या िजस पर वाद दायर ढकया जा सकेगा।

(9) िर्वि्वालय राज्य सरकार अथवा केउ सरकार से ढकसी भी ःकार के अनुदान अथवा

िवृतीय सहायता ःािर् नहल कर सकथगे।

बशतः ढक राज्य सरकार अथवा केउ सरकार अनुदान या अज्य तरीके से

िवृतीयसहायता दे सकती है:

(a) शोध िवकास और अज्य गितिविधय के िलए जैसे राज्य सरकार के अज्य संगठन

कोिवृतीय सहायता उपलध करायी जाती है अथवा

(b) िविश्व-शोध अथवा कायक्रम आधाऱरत कोई गितिविध;

4. िर्वि्वालय कऽ सपित एवं इसके अनुःयोग

(1) िर्वि्वालय कऽ ंथापना हो जाने पर भूमि और अज्य चल एवं अचल सपितयाँ, जो

झारखण्ड

राज्य मथ िर्वि्वालय के उेय (पूत) के िलए अधऴिहत, सृजित, विथत

या िनमत कऽ जाती

ह., वे िर्वि्वालय मथ िनिहत हगी।

(2) िर्वि्वालय ळऱऱा भूमि, भवन और अज्य अधऴिहत सपितयाँ

ढकसी अज्य उेय के िलए इंतेमाल नहल हगी िसवा िजस उेय के

िलए वे अधऴिहत कऽ गयी ह।

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

(3) विविधालय कऽ चल अथवा अचल संपितय का ँबंधन शासी िनकाय द्वारा विनियम मं ँद

रीति के अनुप ङकया जायेगा।

(4) उप धारा-(1) के अतगत विविधालय के नाम से हंतांतरत संपित को विविधालय के विघटन

अथवा समापन के फलवप िनधांतरत ढंग से िनयमावली मं वणत तरीके से

ंयु ङकया जाएगा।

5. विविधालय के िनबं धन

(1) विविधालय के ावसायिक पांम, यथा-अभयं एवं ँौोगिकऽ, िचकसा-शां, ँबंधन

आद के िलए िर्ण-शु, क का िनधांतरण विविधालय के द्वारा

रायसरकार द्वारा अधसूचित

समय-समय पर िनयामक िनकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पयवेण मं ङकया जाएगा।

(2) विविधालय मं नामांकन पूरी तरह योयता के आधार पर होगा। विविधालय मं नामांकन कऽ

योयता का िनधांतरण ँांक या अहता परीं मं ँां ड और

पांेतर और अितर पांचयां

गितिविधय अथवा राय ँतर पर विविधालय या विविधालय के संगठन या

राय सरकार के

कसी अभकरण द्वारा समान पांम के िलए संचालित ँवेश परीं मं

ंां अंक या ड के

आधार पर ङकया जाएगा।

बशतः एक विविधालय के ावसायिक शिक्षण महाविद्यालय

अथवा संस्थान

नामांकन नियंत्रीनिकाय के ावधान द्वारा शासित/नियमित हो।

(3) निधन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए

विविधालय को शिक्षण शुल्क में पूरी

सहायता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृत्ति के अनुमित देनी होगी।

निधनता तथा आर्थिक

दृष्टि से पिछड़े वर्ग के कसौटी का निधाकरण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ठकया जा सकेगा।

(4) विविधालय के विद्यार्थियों के कुल संख्या के कम से कम पचास प्रतिशत

सीट पर झारखण्ड राज्य

के अधवासी विद्यार्थियों के लिए आरिक्त करने का ावधान विविधालय को करना होगा। सीट

के आरण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी

आदेश के द्वारा ठकया

जायेगा।

(5) विविधालय को विविधालय के शिक्षिकेतर पद के कम से कम पचास

प्रतिशत शिक्षिकेतर पद को

झारखण्ड राज्य के अधवासी लोग के लिए आरिक्त करने का ावधान रखना

होगा। सीट के

आरण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी

आदेश के द्वारा ठकया

जायेगा।

- (6) विविध विद्यालय को अकादमिक ंतर को बनाये रखने के िलए यथे/पयाभूत संया मः
शिक एवं

अधिकांश कऽ िनयुि करनी होगी और यह सुनिित करना होगा ःक उन
शिक या

अधिकांश कऽ योयता ंसंगिक िनयामक िनकाय ंसारा िनधाभूत
मानक से िन न हो।

- (7) विविध विद्यालय को विविध विद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विाथय एवं
अयपणधांश के िहत मः

सावभूजिनक करनी होगी, जैसे ःक संचालित पाऽम, अलग-अलग कोट (ेणी) के
तहत सीट, शुऽक

एवं अय पऽर य, ंदत सिलयत एवं सुख सुविधाएँ, उपलध संकाय/ंयापक
वगभूत एवं अय

ंसंगिक सूचनाएँ।

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

7

- (8) पहरिनयम मः वणत रीित के अनुप विविध विद्यालय ंयेक अकादमिक

वषभूत मः उपाधि, िडलोमा ंदान करने एवं अय उंय से दींांत
समारोह आयोजित कर सकेगा।

- (9) विविध विद्यालय को ंथापना के पाँच वष के भीतर र्तीय मूयांकन एवं ंयायन पहरषद्
(NAAC)

से ंयायन ंा करना होगा और भारत सरकार कऽ अय िनयामक संथाएँ, जो

विविध विद्यालय ंसारा संचालित पाऽम से सऽब ह., के ंसारा ंद

ड कऽ सूचना राय सरकार को देनी होगी।

विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे ऋणायन का नवीकरण कराना होगा।

(10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम कऽ अनुसूची 'A' मऽ लिखित शतक और भारत सरकार कऽ नियामक संस्था के नियम, विनियम, मानदण्ड आदि का इन संस्था द्वारा ऋण संचालित तथा सहयोग व कर्तव्य के निरूपण एवं कायदा को जारी रखने के लिए उन संस्था को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा ऋणसार एवं ऐसी अधिगम कऽ शाखा के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, गीर्ण तथा कौशल को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह ऋण्य करेगा ऽक विद्यालय तथा शिक्षक को निरालिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायः:-

(a) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षण मऽ पुनर्नमऽण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, ऋणशिक्षण तथा

अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित, सिमित अधिगम, सतत् शिक्षण एवं अऽय तरीके तथा एकऽकृत एवं ऋणव का हितकर विकास;

(b) विविध अनुशासन मऽ अण्ययन;

(c) अंतर अनुशासनिक अण्ययन;

(d) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा

अंतरराष्ट्रीय मेल मिलाप एवं नीतिशास्त्र।

7.

अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा

ठकसी भी िको को िर्वि्वालय के ठकसी कायाभ्णलय अथवा उसके ठकसी अउय
 ेअधिकार कऽ सदंयता से अथवा ठकसी िडली, िडलोमा अथवा अउय अकादिमक
 वैशिष्ट पाम मऽ नामांकन से ँलग, मत, वगभ्ण, जाति, जउम के ठथान और धाःमक िर्वास
 अथवा राजनीतिक या अउय मतवाद के आधार पर पंोपात या भेदभाव कर वंचित नहऽ ठकया
 जाएगा।

8. िर्वि्वालय के कायभ्ण एवं शियाँ

(i) िर्वि्वालय का ेअशासन एवं ेअबंधन, इसके अंगीभूत महावि्वालय का ेअशासन
 एवं ेअबंधन तथा

शोध, िशिोण, ेअशिोण के केउो का िवंतर एवं सतत् िशिोा, दूरंथ अधगम
 एवं ई-लङनग के
 िवंतर एवं पञ्च को इसके झारखण्ड राउय मऽ अविंथत पहरसर मऽ संचालन व
 ेअबंधन;

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

(ii) िवोान, ेअौोोगिकऽ, मानिवकऽ, समाज िवोान, िशिोा-शाथ, ेअबंधन,
 वाणिउय, िविध, फामअसी,

वाःय सेवा एवं अउय ेअेउो मऽ शोध, उ िशिोा, ावसायिक िशिोा,
 िशिोण- ेअशिोण, सतत्

िशिोा, दूरंथ अधगम एवं ई-लङनग के संसाधन को उपलभ्ध कराना;

(iii) शैिोिक ेअौोोगिकऽ, िशिोण एवं अधगम ेअऽया मऽ नवाचारी ेअयोग, रक्षीय
 एवं अउतररक्षीय

संस्था के साथ सहयोग एवं वैसी संस्था को संयुक्त कार्यक्रम का अंश देना

जिससे शिर्षा के

वितरण एवं अंतरराष्ट्रीय मानक को विकसित एवं अंश करने मं; निरंतरता रहे;

(iv) शिर्षा अंशदान करने मं लचीलेपन के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं अंशाली मं इलेक्ट्रॉनिक

एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;

(v) परीक्षा का आयोजन तथा एकसीटिंग के नाम विविध विद्यालय द्वारा तय शतक के साथ उपाधि,

डिप्लोमा या अंशमाण-पत्र और अंश अकादमिक विशिष्टता अंशदान करना अथवा

विनियमन मं वंणत

तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या अंशमाण-पत्र और अंश अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

(vi) फेलोशिप (शिर्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार अंशपित एवं अंशदान करना;

(vii) पद्धतिमय मं वंणत तरीके के अनुसूप मानद उपाधि या अंश विशिष्टता अंशदान करना;

(viii) उपाध्यक्ष कक्ष अंशान्ति मं आवश्यक सहायता के लिए अंकूल, केअ, संस्थान, महाविद्यालय कक्ष

थापना और विविध विद्यालय के मतानुसार कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम का आयोजन;

(ix) विविध विद्यालय के मतानुसार शिर्षा अंशदान करने व अंशयोजन के अंशोपसाहन के लिए एकसीट

महाविद्यालय, केअ, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत

महाविद्यालय, केअ, संस्थान कक्ष अंशपना करना;

(x) शोध, शिर्षक सामग्री एवं अउय काय के लिए मुँण, ँकाशन एवं पुनरुपादन हेतु

अबधन

एवं अदशभानिय, सलमेलन, कायभानशाला एवं संगोर्ध के आयोजन;

(xi) णान संसाधन केउँ कऽ ंथापना;

(xii) विणान, ँरौर्गिकऽ, मानिवकऽ, समाज विणान, शिर्षक, अबधन,

वाणिज्य, विविध, फामलसी,

वाःय सेवा एवं अउय सब ँरे मथ अनुसंधान तथा शैर्षक कायभानम का

अायोजन एवं

दायिव वहन करना;

(xiii) समान उर्ेय के लिए ढकसी शैर्षक संथान के साथ सहयोग व संबता;

(xiv) विविर्वालय के उर्ेय कऽ अर्ि के लिए आभासी (वचुभानल) पहरसर समेत

पहरसर

कऽ ंथापना;

(xv) पेटेट अकृति के शोध, योजना अधिकार एवं ऐसे समान अधिकार के साथ र्म

अर्धिकार से अनुसंधान के संबंध मथ पंजीकरण का दायिव लेना;

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

9

(xvi) विविर्वालय के आंशिक अथवा पूणभान उर्ेय कऽ अर्ि हेतु दुनिया के ढकसी भी

हिंसेकेशैर्षक एवं

अउय संथान, विविर्वालय के साथ विर्वाथय, शोधथय, शिर्षक,

कमभानाचारय के आदान-

अदान के ँरारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;

(xvii) अनुसंधान, शिक्का, परामर्श तथा इस प्रकार कइ अइय सेवाएँ देना, जो विविध विद्यालय के आयोजन के लिए आवश्यक हो;

(xviii) शिक्का, शोधार्थी, शासक एवं विद्यालय, औद्योगिक, मानविक, समाज विद्यालय, शिक्का, संबंधन, विविध, वाणिज्य, फार्मासी, स्वास्थ्य सेवा एवं सार्वजनिक के विशेषज्ञों के बीच विविध विद्यालय के लिये कइ कार्यों के लिए संबंध बनाये रखना;

(xix) महिला एवं अइय वंचित विद्यार्थी के लिए विविध विद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष वंथा करने पर विचार;

(xx) विविध विद्यालय के ऋण का नियमन, विद्युत का संबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

(xxi) विविध विद्यालय के उद्योग एवं लिये कार्यों के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल संपत्ति, उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं अइय संसाधन को वसाय, उद्योग, समाज के अइय वर्ग, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन अथवा ठकसी अइय द्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में कार्या करना;

(xxii) विद्यार्थी के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्का तथा कमर्शियल के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं वंथा;

(xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यार्थी एवं अतिरिक्त पाठ्यार्थी गतिविधियों कइ उद्देश्य के लिए, केन्द्र,

पहरसर, सभागार, भवन, इंटरडियम का निर्माण, संबंधन तथा रख-रखाव;

(xxiv) विविध विद्यालय के निवासी विद्यार्थी, शिक्षक तथा कमजोर छात्रों के लिए

अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्धन हेतु पर्याप्त वेतन, नियंत्रण तथा नियमन;

(xxv) परिनियम द्वारा निधात फंड एवं अथ शेष क तय करना, मांगना तथा प्रसार करना;

(xxvi) फैलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अथ पुरस्कार क स्थापना;

(xxvii) विविध विद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने क दृष्टि से ढकसी भूमि या भवन

को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहार वसीयत, विरासत या अथ तरीके से कायदा हेतु

प्रसार कर

सकेगा और यह

उन नियम व शर्त के प्र मथ ंवीकायदा हो सकता है, जिससे ढकसी भवन

को बनाने या कायदा

करने, उसमथ परवर्तमान करने और रख-रखाव हेतु उचित हो;

(xxviii) विविध विद्यालय के िहत, गतिविधियों एवं उर्ेय क संगित क दृष्टि से जो माथ

हो, उसके अनुप्र विविध विद्यालय क चल या अचल संपत्ति या उसके ढकसी िहंसे को

बेचने, विनियम, पट्टा या अथ तरीके से प्रबंधित करना;

झारखंड गजट (असाधारण) गु+वार, 11 अक्टूबर, 2018

(xxix) निमात्राण और समथान, कटौती और वातात्रा, वचनपू नोट, विनियम

बिल, चेक और अथ विनियम उपकर आकषत और ंवीकार करना;

(xxx) विविध विद्यालय के सभी खच को पूरा करने के लिए विविध विद्यालय क निध को

बढ़ाना और बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपू नोट या अथ दायित्व या

प्रतिभूति क स्थापना या संपूर्ण अथ विविध विद्यालय क ढकसी

संपिठ और पहरस-पिठ अथवा िबना ढकसी ंकृतिभूति और माउय िनयम

और शत के अनुप करना;

9. स-बता के अवरो

- (1) िविविंालय को ढकसी महािविंालय या संंथा को स-बता देने का िवशेषाधिकार नहल होगा।
- (2) िविविंालय अनुदान आयोग अथवा सरकार ंद्वारा ंथापित ऐसे अउय िनयामक िनकाय अथवा केउ या राउय सरकार, जैसा भी हो, के ंद्वारा पूवका ंवीकृति के पू ात ही िविविंालय अपने पहरसर के अलावा कोई दूरवतठ पहरसर, अपतठ पहरसर, अययन केउ, परींा केउ झारखण्ड राउय के अउर या बाहर शु कर सकेगा।
- (3) दूरंथ ंणाली से पाम कऽ शुआत केवल िविविंालय अनुदान आयोग अथवा सरकार ंद्वारा ंथापित ऐसी िनयामक संंथा कऽ पूवका ंवीकृति के बाद कऽ जाएगी।

10. आगंतुक (िविजटर

- (1) झारखण्ड के राउयपाल िविविंालय के िविजटर (आगंतुक) हगे।
- (2) आगंतुक (िविजटर) जब दींांत समारोह मऽ िडली (उपाधि), िडलोमा, चाटकर, ओहदा (पदनाम) और ंमाण-पू ंदान करने के िलए मौजूद रहंगे तो उसकऽ अयंता करंगे।
- (3) िविविंालय अथवा िविविंालय ंद्वारा संपोषित ढकसी संंथान के िशिंा के ंतर, अनुशासन,

िशिाचार और समुचित ढदयाशीलता को सुनिंमण/दौरे का अधिकार होगा।

त करने कऽ दृष्टिसे आगंतुक को विविध विद्यालय के

विद्यालय के अधिकारी

11. विविध विद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (a) कुलाधिपति | (b) कुलपति |
| (c) अति-कुलपति | (d) निदेशक/अध्यापक |
| (e) कुलसचिव | (f) मुख्य विद्वान एवं लेखा पदाधिकारी |
| (g) परीक्षा नियंत्रक | (h) छात्र कल्याण संकायार्थी |
| (i) संकायार्थी | (j) कुलानुशासक और |
| (k) विविध विद्यालय मध्य अथवा ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे। | |

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अक्टूबर,2018

11

12. कुलाधिपति:-

- (1) कुलाधिपति कऽ नियुक्ति अवधिका निम्नलिखित द्वारा पाँच वर्ष कऽ अवधि के लिए आगंतुक (विजटर) के अनुमोदन के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों तथा एतत्संबंधी नियम एवं शर्तों के अनुरूप कऽ जाएगी।
- कायधिकाकाल पूरा होने के पूर्व किये जा सकेंगे।

पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक कऽ सलाह के बाद अवधिका निम्नलिखित द्वारा पुनर्नियुक्ति

- (2) कुलाधिपति अपने कायधिकालय पद के अधिकार से विविध विद्यालय के अध्यापक होंगे।
- (3) कुलाधिपति शासी निम्नलिखित कऽ बैठक कऽ आयोजित करेंगे और जब आगंतुक (विजटर) मौजूद न हों रहेंगे तब उपाधि (डिप्टी), डिप्टीलोमा या अथवा अकादमिक विस्तार अध्यापन करने हेतु दीर्घांत समारोह कऽ आयोजित करेंगे।

(4) कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित वरतभ्रुक िनकाय को संबोधित कर अपने पद से इतीफा दे

सकते ह।

(5) कुलाधिपति को िलिखित अधिकार हगे, यथा:-

(a) ढकसी भी जानकारी या अभिलेख कऱ माँग करने;

(b) कुलपित कऱ िनयुि;

(c) इस अधिनयम के ावधान के अनुप कुलपित को हटाने और

(d) इस अधिनयम या पहरिनयम के ँद्वारा ादऱ अय शियाँ।

13. कुलपित:-

(1) कुलपित कऱ िनयुि कुलाधिपति िर्विवालय अनुदान आयोग ँद्वारा

िनधाभ्रुक ढरत योयता के

अनुप करगे और ये पाँच साल कऱ अविध के िलए अपने पद पर बने रहगे। बशतऱ ढक कुलपित पाँच

वषभ्रुक कऱ अविध पूरी होने के पु

ात् पाँच वषभ्रुक के एक और कायभ्रुकाल के िलए पुननयुि के पा हगे।

शतभ्रुक यह रहेगी ढक कुलपित के ाप मऱ िनयुि 70 वषभ्रुक कऱ आयु

पूरी करने के बाद अपने पद से, कायभ्रुकाल के दौरान या िवताहरत कायभ्रुकाल से सेवानिवृत हो जाएगा।

(2) कुलपित िर्विवालय के मुय कायभ्रुकारी और अकादिमक अधिकारी हगे

और िर्विवालय के मामल मऱ सामाय अधीण और िनयंण का ायोग करगे

तथा िर्विवालय के िविभु ाधिकार ँद्वारा िलए गए फैसल पर अमल करगे।

(3) आगतुक (िविजटर) और कुलाधिपति कऱ गैर मौजूदगी मऱ िर्विवालय के दीांत समारोह कऱ

अयता करगे।

- (4) कुलपित यऽद यह अनुभव करुं ऽक ऽकसी मामले पर तऽकाल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विविध विद्यालय के ऽकसी ऽकाधिकार का इस अधिनियम के तहत ऽदश शिष्य का इंतेंमाल कर सकते ह. और उस ऽकाधिकार को संबं मामले मऽ कृत कार्रवाई कऽ जानकारी दे सकते ह.।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गु+वार, 11 अक्टूबर, 2018

बशतऽ ऽक विविध विद्यालय का ऽकाधिकार या विविध विद्यालय कऽ सेवा का अऽय

ि यऽद

कुलपित ऽदऽारा कृत कार्रवाई से ऽथित है तो इस उप धारा के तहत इस िनणऽय के संऽेऽित होने कऽ

ितिथ के एक माह के भीतर कुलाधिकारित के समीं अपील कर सकता है। कुलाधिकारित, कुलपित ऽदऽारा

कऽ गयी कार्रवाई को संपु, संशोधित या पऽरवर्तित कर सकते ह.।

- (5) कुलपित ऐसी शिष्य का ऽयोग करुंगे और इस तरह के अऽय कायऽ करुंगे जो विहित ऽकया जाय।

14. कुलपित कऽ पदऽयुति

- (1) कुलाधिकारित को यऽद ऽकसी समय ऽकसी जाँच के पू ात् आवश्यक लगे या ऽतीत हो ऽक कुलपित:

(a) इस अधिनियम, पऽरिनियम, अऽयादेश के तहत ऽदश कृतऽा के

िनवऽहन मऽ विफल रहे हऽ;

अथवा

(b) विविधालय के विहित के विपरीत पूर्वाज्ञा यह से उत्तर होकर कायज्ञा ठकये ह, या

(c) विविधालय के मामल को सुलझाने मः अम ह, तो कुलाधिपति इस बात के होते

अए भी ठक कुलपित का कायज्ञाकाल पूरा नहए अआ है, कारण बताते अए

निधाज्ञाहरतितिथ

से पद से इंतीफा देने के लिए लिखत आदेश दे सकते ह।

(2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कारावाइ के ठकसी उत्ताव कऽ सूचना ठदए बिना कोई

आदेश पाहरत नहए ठकया जाएगा, उत्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपित को ठदया जाएगा।

15. उत्ति-कुलपित

(1) उत्ति-कुलपित कऽ नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से कऽ जाएगी और वह ऐसी शिष्य का

उयोग करेगा तथा ऐसे काय का निरुपादन करेगा जो विहित ठकया जाय।

(2) उत्ति कुलपित उप धारा-1 के तहत नियुक्ति एक प्रोफेसर के अप मः अपने कतज्ञा के अलावा अपने कतज्ञा का निवृत्त करणगे।

(3) उत्तिकुलपित कुलपित को उनकऽ आवयकतानुसार उनके कतज्ञा के निवृत्त मः सहायता करणगे।

(4) उत्तिकुलपित अवतज्ञाक निकाय द्वारा निधाज्ञाहरत राशि मानदेय के अप मः उत्तर करणगे।

16. निदेशक/०२ धानाचाय

निदेशक/०२ धानाचाय कऽ नियुक्ति निर्देशक से तथा ०२दृ शिष्य का ०२योग कर कऽ जा सकेगी।

17. कुलसिचव :-

(1) कुलसिचव ०२वतऽक निकाय के अ॥य॥ ॥॥॥॥ पहरिनयम मऽ निर्देशक ०२वधान के अनुसार नियुक्ति कये

जाएंगे। कुलसिचव विविध विद्यालय अनुदान आयोग ॥॥॥॥ निधाऽहरत योग्यता को धारण करणगे।

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

13

(2) कुलसिचव को विविध विद्यालय कऽ ओर से अभिलेख, दस्तावेज को अभि० माणित करने, ०२माण-प०

पर हस्ता० करने तथा समझौता करने कऽ शिष्य होगी तथा वे ऐसी दूसरी शिष्य का ०२योग एवं

काय को पूरा करणगे जो उनके लिए निर्देशक कया गया हो।

(3) कुलसिचव कायऽकारी पहरषद् एवं अकादिमक पहरषद् के पदेन सद०य सिचव ह०गे लेकनउ३ह० मत देने

का अधिकार नह० होगा।

18. विद्व तथा लेखा अधिकारी

(1) ०२वतऽक निकाय के अ॥य॥ ॥॥॥॥ मु०य विद्व तथा लेखा पदाधिकारी कऽ नियुक्ति इस ०२कार कऽ जाएगी,

जैसा पहरिनयम मऽ निर्देशक हो।

(2) मु०य विद्व एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शिष्य का ०२योग तथा दा०य०व का निवऽहन कर सकणगे जैसा

०२क पहरिनयम मऽ निर्देशक है।

19. परी०ा नियुक्ति

(1) परीक्षा नियंत्रक विविध विद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा पहरिनयम के अनुसार

कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगे:-

(a) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;

(b) सत गोपनीयता का दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन का प्रबंध करना;

(c) निधाकाल पर समय-सादरणी के अंतर्गत उच्च पुस्तिका के मूल्यांकन का प्रबंध

करना;

करना;

(d) परीक्षा-प्रणाली का निर्णय और विषयनिर्देश को तैयार बनाने तथा विभाजन

का

योग्यता के सही आकलन का दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत समीक्षा करना;

(e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना

जो परीक्षा से संबंधित हों।

20. अय अधिकारी

छात्र कक्षा, संकायार्थी, संकायार्थी और मुख्य कुलानुशासक सहित विविध विद्यालय के

अय

अधिकारियों के दायित्व, शिष्ट और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

21. विविध विद्यालय के अधिकार:

विविध विद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथा-

- (a) शासी िनकाय
- (b) ँबंधन बोडभा

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

- (c) अकादिमक पहरषद्
- (d) िवदु सिमित
- (e) योजना बोडभा
- (f) वैसे अउय सभी ँाधिकार, जो पहरिनयम के ँद्वारा िर्विव्ालय के ँाधिकार घोषित
कये गये ह।

22. शासी िनकाय

- (1) शासी िनकाय के िन्िलिखत सदंय हगे, यथा-
 - (a)कुलाधिपित;
 - (b)कुलपित;
 - (c)सरकार के सिचव, उ एवं तकनीक शिा िवभाग, झारखंड अथवा उनका
ंतिनिध;
 - (d)ंवतभाक िनकाय ँद्वारा नामित पाँच ि, िजनमः से दो ँयात
शिािवद् हगे;
 - (e)कुलाधिपित ँद्वारा नामित िर्विव्ालय के बाहर से एक ि, जो ँबंधन
और ँौोगिक के िवशेष के रूप मः हगे।
 - (f)कुलाधिपित ँद्वारा नामित एक िवदु िवशेष।
- (2) शासी िनकाय िर्विव्ालय का सव ँाधिकार एवं मुय शासी िनकाय होगा।
इसक
िन्िलिखत शियाँ हगी, यथा:-
 - (a)िनयम, पहरिनयम, अधिनयम, िविनयम अथवा अयादेश का ँयोग करते ए

िविव्ालय के काय को िनयंित, िनदशित एवं संचालित करना;

(b) विविध विद्यालय के अग्र्य निणयन कऽ समीक्षा करना यऽद वे अधिनयम, पहरिनयम,

अज्ञादेश, विनयन या नियमावली के अवधान के अनुप नहऽ हो;

(c) विविध विद्यालय के वाषक उत्तिवेदन तथा बजट को अनुमोदत करना;

(d) विविध विद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विवृत नीतय का निमाभण;

(e) विविध विद्यालय के विघटन के लिए अवतभणक निकाय को अनुशंसा करना, यऽद संपूण

व्यास के बाद भी विविध विद्यालय ठीक ढंग से कायभण संपु करने कऽ िंथित

मऽ नहऽ हो;

(f) पहरिनयम द्वारा निंद अग्र्य शिष्य का वयोग करना।

(3) शासी निकाय कऽ बैठक एक कैलण्डर वषभण मऽ कम-से-कम तीन बार होगी।

(4) बैठक का कोरम चार होगा;

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार, 11 अ, टूबर, 2018

बशतऽ उ एवं तकनीकऽ िशिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सिचव या उनकऽ

अनुपिंथित मऽ

निदेशक, उ िशिक्षा वयोगक बैठक मऽ उपिंथित ह, िजसमऽ सरकारी नीतय या

निदऽश से संबंधित

निणयन

िलये जाने ह।

23. वबंधन बोडभणः

(1) वबंधन बोडभण नििलिखत सदंय के योग से गठत होगा, यथा-

(a) कुलपित;

(b) सरकार के सिचव, उ एवं तकनीकऽ िशिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके

नामित;

(c) ँवतङ्गक िनकाय ँःःारा नामित शासी िनकाय के दो सदंय;

(d) ँवतङ्गक िनकाय ँःःारा नामित तीन सदंय, जो शासी िनकाय के सदंय नहः हः;

(e) िशःक के बीच से ँवतङ्गक िनकाय ँःःारा नामित तीन सदंय;

(f) कुलपित ँःःारा नामित दो िशःक।

(2) ँबंघन बोडङ्ग के अयः कुलपित हःगे।

(3) ँबंघन बोडङ्ग कः शिःयँ एवं कायङ्ग पहरिनयम मः जैसा िनंद है, के अनुप होगा।

(4) ँबंघन बोडङ्ग कः बैठक का कोरम पाँच होगा;

बशतः ःक सरकार के सिचव, उः एवं तकनीकः िशःा िवभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकः

अनुपिंथित मः िनदेशक, उः िशःा ँयेक बैठक मः उपिंथित हः; िजसमः सरकार कः नीतिय/िनदःश से

संबंघित िनणङ्गय िलये जाने हः।

24. अकादिमक पहरषद्

(1) अकादिमक पहरषद् कुलपित तथा वैसे सदंय के योग से बनेगा, जैसा पहरिनयम मः िनंद है।

(2) अकादिमक पहरषद् के अयः कुलपित हःगे।

(3) आकादिमक पहरषद् िर्विःालय कः मुय अकादिमक िनकाय होगी, जैसा ःक अधिनयम,

पहरिनयम, अयादेश मः ँावधान है और यह िर्विःालय कः अकादिमक नीतिय का

संयोजन तथा पयङ्गवेःण करेगी।

(4) अकादिमक पहरषद् कः बैठक का कोरम पहरिनयम के िनदःश के अनुप होगा।

25. िवःु सिमित

- (1) विद्युत् सिमित विविध विद्यालय कऽ मुख्य विद्युत् निकाय होगी, जो विद्युत् संबंधी मामलऽ कऽ देख-रेख करेगी।
- (2) विद्युत् सिमित का संविधान, शिऽयाँ और कायऽन के अनुऽप हऽगे जैसा कऽ विहित ढकया जाय ।

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

26. योजना बोड

- (1) योजना बोडऽन विविध विद्यालय का ँधान योजना निकाय होगा और यह सुनिऽत करेगा ढक बुनियादी

ढाँचा और अकादिमक समथऽन ँणाली विविध विद्यालय अनुदान आयोग तथा अऽय

पडरषदऽ ँनऽरा

निधाऽनऽरत मानदंडऽ को पूरा करती है।

- (2) योजना बोडऽन का संविधान, उसके सदऽयऽ का कायऽनकाल तथा उनकऽ शिऽयऽ एवं कायऽ का

निधाऽनऽरण वैसा होगा जैसा कऽ विहित ढकया जाय ।

27. अऽय ँाधिकार

विविध विद्यालय के अऽय ँाधिकारऽ का गठन, शिऽयाँ तथा कायऽन वैसा होगा जैसा कऽ विहित ढकया जाय।

28. ढकसी ँाधिकार अथवा निकाय कऽ सदऽयता के िलए अयोऽयता

कोई ि विविध विद्यालय के ढकसी ँाधिकार या निकाय कऽ सदऽयता के योऽय नहऽ होगा, यऽद वहः

- (a) यऽद वह अंथऽ मानस का है और उसे सर्ऽम ऽयायालय ँनऽरा ऐसा घोऽषित ढकया गया है;
- (b) यऽद अमुऽ ढदवाऽलिया है;
- (c) यऽद नैतिक ँखलन का अपराधी पाया गया है;

- (d) ढकसी परीक्षा के संचालन मऒ अनुचित ँ वहार करने अथवा ँऒोसाहित करने के िलए कहल भी,
ढकसी ँप मऒ दंडित ढकया गया है।

29. विविर्विर्वालय के ँऒाधिकार अथवा िनकाय के गठन या कायऒ्णवाही को अमाऒय नहल करऒगी

विविर्विर्वालय के ढकसी ँऒाधिकार कऒ कायऒ्णवाही िसफऒ्ण िसलए अमाऒय नहल कऒ जायेगी ढक विविर्विर्वालय के ढकसी ँऒाधिकार या संगठन कऒ ढरिऒ अथवा संविधान मऒ कोई दोष है।

30. सिमितयऒ का गठन

विविर्विर्वालय के ँऒाधिकार ऐसी शतऒ के साथ जो विवशेष काम के िलए आवऒयक हऒ तथा जो पढरिनयमऒ

द्वारा अनुमोढदत हऒ, ऐसी सिमितयऒ का गठन कर सकऒगे।

अऒायादेश और िविनयम

31. ँऒथम पढरिनयम

(1) िस अधिनयम के ँऒावधानऒ तथा िसके अंतगऒ्णत बनाये गए िनयमऒ के अनुकूल पहला पढरिनयम

िनिलिखत मामलऒ मऒ से सभी या ढकसी ँक का िनधाऒ्णरण करेगा, यथा-

(a) विविर्विर्वालय के ँऒाधिकारऒ और अऒय िनकायऒ के िलए समय-समय पर गठन,

शिऒयऒ और कायऒ का िनधाऒ्णरण;

(b) कुलाधिपित, कुलपित कऒ िनयुऒिऒ कऒ शतऒ और उनकऒ शिऒयऒ तथा अधिकारऒ का

िनधाऒ्णरण;

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

(c) कुलसिचव और मुऒय विवऒ तथा लेखा पदाधिकारी कऒ िनयुऒिऒ कऒ ँऒऒया और शतऒ

तथा उनकऽ शिष्य और कायभङ्ग का निधाभङ्गरण;

(d) अय अधिकांश तथा शिष्य कऽ नियुक्ति कऽ पति और शत तथा शिष्य और कायभङ्ग का

निधाभङ्गरण;

(e) विविधालय के कमभङ्गचांश कऽ सेवा-शत का निधाभङ्गरण;

(f) कमभङ्गचांश अथवा विवाह्य और विविधालय के बीच एकसी प्रकार के विवाद कऽ

निधित मऽ मयंथता कऽ उद्घाटन का निधाभङ्गरण;

(g) मानद उपाधियाँ उदान करना;

(h) विवाह्य के शिष्य शुद्ध कऽ अदायगी मऽ छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप उदान

करने कऽ उद्घाटन का निधाभङ्गरण;

(i) सीट के आरंभ के नियम सहित उद्देश कऽ नीति का निधाभङ्गरण; तथा

(j) विवाह्य से लिया जाने वाला शुद्ध।

(2) विविधालय का पहला पद्धतिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और
वीकृति हेतु

राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

(3) विविधालय द्वारा समर्पित किए गए पहले पद्धतिनियम पर राज्य सरकार विचार
करेगी और

यथासंभव इसकऽ उद्देश के साथ उदान के भीतर इसकऽ वीकृति, संशोधन अथवा
बिना

संशोधन के जैसा वह आव॑यक समझे, देगी।

- (4) रा३य सरकार ँव॑कृत पहले प॒रिनयम॑ पर वि॒वि॒व॑ालय अपनी सहमित सं॒वे॒षित करेगा,

अथवा रा३य सरकार ँव॑कृत उप धारा-3 के अंतग॒भूत॑ ढकये गये ढकसी संशोधन या सभी संशोधन॑ को

नह॒ल लागू करने पर कारण बतायेगा। रा३य सरकार वि॒वि॒व॑ालय के सुझाव॑ को मा३य या अमा३य

कर सकती है।

- (5) रा३य सरकार ने पहले प॒रिनयम॑ को िजस ३प म॑ अंततः ँवीकार ढकया है उसे शासक॒इय

राजप॒म॑ म॑ ँका॑शित करेगी और यह ँकाशन क॒इ तिथि से लागू माना जाएगा।

32. परवत॒ट प॒रिनयम॑

- (1) इस अधिनयम और इसके बाद बनाये गये िनयम॑, वि॒वि॒व॑ालय के परवत॒ट प॒रिनयम॑ म॑

ि॒नि॒लिखत सभी या ढकसी एक के बारे म॑ व॑ंथा दे सकता है, यथा-

(a) वि॒वि॒व॑ालय के नये ँका॑धिकार॑ का सृजन;

(b) लेखा नी॑ति और वि॒वृ॒थीय॑ ँ॒ड॒या;

(c) वि॒वि॒व॑ालय॑ के ँका॑धिकार॑ म॑ िश॑क॑ का ँ॒ति॒निध॑व;

(d) नए वि॒भाग॑ का िनमा॒भूत॑ण और वत॒भूत॑मान वि॒भाग॑ का उ॒मूलन॑ अथवा

पुनर्ग॒ठन॑;

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

(e) पदक॑ और पुर॑ंकार॑ का िनधा॒भूत॑ण;

(f) पद॑ के िनमा॒भूत॑ण और वि॒लोपन॑ क॒इ ँ॒ड॒या;

(g) शुल्क का पुनरीक्षण;

(h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा

(i) अतः सभी मामलों का पद्धतिनियम द्वारा निधाकरण, जो इस अधिनियम में

वर्णित व्यवधान के

अंतर्गत आवश्यक हों।

(2) पहले पद्धतिनियम से इतर विविधालय के पद्धतिनियमों का निमाकरण शासी निकाय की सहमति से

वैधानिक बोर्ड द्वारा ठकया जाएगा।

(3) उप धारा (2) के अंतर्गत निम्न पद्धतिनियम को राज्य सरकार के समक्ष रखकर ठकया जाएगा, जिसे वह

वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श,

पद्धतिनियम की ओर की

तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और पद्धतिनियम में ठकये

गये पद्धतिनियम के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर

हटोपणी के साथ उसे

वापस कर देगा।

(5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी हटोपणियों पर विचार करेगी तथा पद्धतिनियमों को बिना

संशोधन अथवा संशोधनों के साथ वीकृत करेगी और इसे शासकिय राजपत्र में

प्रकाशित करायेगी

जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

33. ँथम अणयादेश

(1) इस अधिनयम के ँवाधान के अधीन िनःमत िनयम, पहरिनयम के तहत,

ँथम अणयादेश सभी

मामले या िनिलिखत मः से कोई एक अथवा सभी कः वंथा कर सकता है,
यथा-

(a) िर्विंवालय मः िर्वंथय का ँवेश और इस ण मः नामांकन;

(b) िर्विंवालय कः िडली, िडलोमा एवं ँमाण पः के िलए अणयन हेतु
पाठयम का

िन्धाकरण;

(c) िडली, िडलोमा, ँमाण पः और अय अकादमिक वैशिः ँदान करने हेतु
अनतम

योयता;

(d) फेलोशिप, छावृि, वजीफा, पदक और पुरंकार हेतु शत;

(e) कायालय के िनयम और परीण िनकाय, परीक तथा मणयंथ कः
िनयुि के तरीके

सिहत परींा का संचालन;

(f) िविभू पाठयम कः परींा, उपाधय और िडलोमा के िलए

िर्विंवालय ँरा

िलया जाने वाला शुःक;

(g) िर्विंवालय के िर्वंथय के िनवास कः शत;

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार, 11 अ, टूबर, 2018

(h) िर्वंथय के िवः अनुशासनामक कारणवाई संबंधी ँवाधान;

(i) विविध विद्यालय के अकादमिक जीवन का उचित के लिए आवश्यकता अनुभव

ठकये जाने पर ठकसी निकाय के सृजन, संयोजन और कायदा पर विचार;

(j) उच्च शिक्षा के अथ विविध विद्यालय एवं संस्थान के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;

(k) ऐसे अथ मामले निजनक वं अयादेश के द्वारा इस अधिनियम के अतगता आवश्यक है;

(2) विविध विद्यालय का अथम अयादेश अबंधन बोड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को अंतुत ठकया जाएगा।

(3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सपे गये अयादेश पर विचार करेगी और

जहाँ तक संभव होगा इसका अाि के साथ ठदन के भीतर वह इसे ंवीकृत करेगी या इसमं संशोधन हेतु सुझाव भी देगी।

(4) कुलाधिपति अयादेश के संदभं मं ठदये गये संशोधन के सुझाव को शािमल करंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा ठदये गये सुझाव को शािमल नह करने के

कारण बताते अे अथम अयादेश को वापस भेजंगे, यठद कुछ हो । राज्य सरकार

इसका अाि के बाद कुलाधिपति का ढटपणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या िबना ठकसी संशोधन के विविध विद्यालय के अथम अयादेश को राज्य सरकार

शासकय राजपू मं अकािशत करेगी, और यह अकाशन का ितिथ से अभावी होगा।

34. परवत अयादेश

- (1) ँथम अण्णयादेश के अलावा अउय सभी अण्णयादेश अकादिमक पहरषद ँण्णारा बनाये जाएँगे जो शासी िनकाय ँण्णारा अनुमोदत ठकये जाने के बाद राउय सरकार के समीँ अनुमोदन हेतु ँउँतुत ठकये जाएँगे।
- (2) उपधारा (1) के तहत अकादिमक पहरषद ँण्णारा सपे गये अण्णयादेश पर जहाँ तक संभव हो राउय

सरकार इसक ँउँाँ के दो माह के भीतर िवचार करेगी और इसे ँवीकृत कर सकती है या इसमँ संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी।

- (3) अकादिमक पहरषद या तो राउय सरकार के सुझाव के अनुप अण्णयादेश को संशोधित करेगी या सुझाव को राउय सरकार को पुनः उसे वापस सपेगी, यठद कोई हो। राउय सरकार अकादिमक पहरषद क ढटपणी पर िवचार करेगी और अण्णयादेश को संशोधन के साथ या िबना संशोधन के शासकय राजपू मँ ँकाशित करेगी, और यह ँकाशन क ितिथ से ँभावी हो जाएगा।

35. िविनयम:-

ऐसे ँउँयेक ँउँाँधिकार और ऐसे ँउँाँधिकार ँण्णारा बनायी गयी सिमितय के िलए शासी िनकाय क पूवँ ँवीकृति से िवँिवँालय के ँउँाँधिकारी इस अधिनयम के

अनुकूल िनयम, पहरिनयम और अण्णयादेश के संगत िविनयम बना सकंगे।

36. िनदश देने के राउय सरकार के अधिकार

- (1) िशँण के ँतर, परीँँा और शोध तथा िवँिवँालय से संबँ ठकसी अउय मामले मँ राउय सरकार ऐसे लोग, िजहँ वह उपयु समझती है, के ँण्णारा मूँयांकन करा सकेगी।

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

(2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ

विश्वविद्यालय को

संकेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारामक उपाय और चयन करेगा ताकि इन

अनुशंसा का

अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कड़ी अनुशंसा

का पालन करने में

उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निदेश दे सकेगी

जैसा वह उपयुक्त

समझे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय

अविलंब करेगा।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

37. स्थायी निधि

(1) उद्देश्य-पूर्व में निर्देशों के साथ चयनित निकाय विश्वविद्यालय के लिए

एक स्थायी कोष की

स्थापना करेगा।

(2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिचय तथा

अनुदेश के

अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के

रूप में

होगा। यदि विश्वविद्यालय अथवा चयनित निकाय इन अधिनियम, परिचय तथा

अनुदेश के

अनुकूल व्यवधान का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि

अथवा इसका

एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा।

(3) विविवालय इस ंथायी कोष से शई आमदनी का उपयोग विविवालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के िलए कर सकेगा, विविवालय के ढदनानुढदन ्र य के िलए नहल।

(4) विविवालय के विवघटन तक ंथायी कोष कऽ रािश ऐसे साधन मऽ िनवेिशत कऽ जाएगी जैसा

सरकार ँनऽारा िनवेश हेतु िनदऽिशत ढकया जाएगा।

(5) दीघाऽाविध कऽ ँतिभूित कऽ िंथित मऽ, ँतिभूितय का ँमाण-पू सरकार के सुरिँत संरँण मऽ रखा

जाएगा और ्र िगत जमा खात के ्रयाज को सरकारी खजाने मऽ जमा ढकया जाएगा। शऽा यह है ढक सरकार के आदेश के िबना यह रािश िनकाली नहल जा सकेगी।

38. सामाऽय िनिध

(1) विविवालय एक कोष कऽ ंथापना करेगा, िजसे सामाऽय कोष कहा जाएगा, िजसमऽ िनंढकत रािशयाँ जमा हगी:

(a) विविवालय ँनऽारा ँाँ िशिँण एवं अऽय शुऽक;

(b) ँवतऽाक िनकाय ँनऽारा ँदऽ कोई भी रािश;

(c) अपने लंय-िसि के ढम मऽ विविवालय के ढकसी भी उपढम, यथा-परामशऽा आढद से ँाँ

कोई भी रािश;

(d) ऽयास, वसीयत, दान, वृिददान और ढकसी भी अऽय ँकार का अनुदानतथा

(e) विविवालय ँनऽारा ँाँ अऽय सारी धनरािश।

(2) सामाज्य कोष का उपयोग िनिलिखत मद मथ ढकया जाएगा, यथा -

(a) इस अधिनयम और पढरिनयम, अयादेश और शासी िनकाय कऽ पूवभा ंवीकृति के साथ

विर्विवालय ढराना िलये गये ऋण तथा उसके ढयाज के भुगतान हेतु;

(b) विर्विवालय कऽ पढरसंपितय के रख-रखाव हेतु;

(c) धारा 37 एवं 38 के अंतगभात िविनःमत िनिधय के लेखा-परीण के िलए भुगतान ढकया गया

शुऽक;

(d) विर्विवालय के पीठ अथवा िवपीठ मथ दायर वाद पर शए खचभा के िनृपादन हेतु ;

(e) अधिकाढरय, कमभाचाढरय, िशीक एवं शोध-अधिकाढरय के वेतन, भङे, भिवृय-निध

अंशदान, ढूँढूटी और अय सुविधा के भुगतान हेतु;

(f) शासी िनकाय, कायभाकारी पढरषद, अकादिमक पढरषद और अय ंवाधिकार तथा ंवतभाक

िनकाय के अय पीठ अथवा ढकसी सीम अधिकारी ढराना ढकये गये याा-

य एवं अय

भङे

के भुगतान हेतु;

(g) फेलोशिप, िनःशुऽक िशीण, छावृठिय, िसंठशटिशप तथा समाज के कमजोर

आथक वगभा

के छाो को ढदये गये पुरंकार और शोध सहायक, ंवशिीु अथवा जैसी

िंथित हो

अधिनियम, पहरिनियम और नियम के अनुकूल ठकसी भी अहङ्गता ॐा

विवाथट के भुगतान

हेतु;

(h) अधिनियम के ॐावधान, पहरिनियम, अयादेश, विनियम के अनुपालन मः

विर्विवालय

ॐारा ॐ य कऽ गयी ठकसी भी रािश के भुगतान हेतु;

(i) ॐवतङ्गक िनकाय ॐारा विर्विवालय कऽ ँथापना और इस संदभङ्ग मः ठकये गये

निवेश कऽ मूल

लागत, जो समय-समय पर भारतीय ँटेट ब.क के ऋण ॐदान कऽ दर से अधिक नहः

हो, के

भुगतान के िलए।

(j) इस अधिनियम के पहरिनियम, नियम, अयादेश के पालन मः विर्विवालय

ॐारा ठकये गये ॐ

य के भुगतान हेतु;

(k) ठकसी संथान ॐारा विवशेष सेवा देने के दाियव, विर्विवालय को ॐबंधन-सेवा

सिहत शासी

िनकाय ॐारा विर्विवालय के िलए ँवीकृत ऐसे ॐहेतु;

य अथवा संबं अय काय के भुगतान

बशतः ठक कुल आवतः.

य और

उस वषङ्ग के िलए िनधाङ्गःरत अनावतः.

य

जैसा

शासी िनकाय ॐारा िनि.

त ठकया गया है, से अधिक

य िबना शासी िनकाय कऽ पूवङ्ग ँ

वीकृति के नहः ठकया जा सकेगा।

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

अंकेऱण एवं वाःषक ॐतिवेदन

39. वाऋषक ंऱितवेदन

विजिविवालय का वाऋषक ंऱितवेदन विजिविवालय ँऱऱारा तैयार ढकया जाएगा ञिसमथ अडय मामल ं समेत, विजिविवालय ँऱऱारा उ ंैय कऱ पूऱत के िलए उठाये गये कदम शािमल ह ंगे और इसे राडय सरकार को स ंपा जाएगा।

40. अंके ंण एवं वाऋषक ंऱितवेदन

(1) विजिविवालय का वाऋषक लेखा ब.लेस शीट सिहत विजिविवालय ँऱऱारा तैयार ढकया जाएगा और वाऋषक लेखा का अंके ंण वषऱ्ण मथ कम से कम एक बार विजिविवालय ँऱऱारा इस उ ंैय से िनयु अंके ंक ँऱऱारा कराया जाएगा।

(2) वाऋषक लेखा कऱ एक ंऱित अंके ंण ंऱितवेदन के साथ राडय सरकार को ंऱंतुत करनी होगी।

विजिविवालय को समेटना

41. विजिविवालय का समापन:

(1) यढद ंऱवतऱ्णक िनकाय िविध स ंमतढंग से इसके गठन तथा िनगमीकरण के ंऱावधान के अडतगऱ्णत ंवयं को भंग करना चाहे तो इसकऱ सूचना कम से कम छह महीने पहले राडय सरकार को देनी होगी।

2) राडय सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) ंऱा करने के पू ंत, जैसी आवंयकता होगी उसके

अनुषप भंग ढकये जाने कऱ ितिथ से विजिविवालय के ंऱशासन कऱ ूवंथा

ंऱवतऱ्णक िनकाय के िवघटन के बाद आखरी सऱ के िवाऱ्थय, जो

विजिविवालय मथ नामांढकत ह., के पा ंऱम पूरा होने तक करेगी और सरकार

ंऱवतऱ्णक िनकाय के ंथान पर विजिविवालय के संचालन के िलए एक

ंऱशासक कऱ

42.

नियुक्ति कर सकेगी, जिसे अवतलक निकाय के अधिकार, कत और कायल सपे
जाएँगे, जैसा इस
अधिनयम मः वलणत है।

विविवालय का विघटन

(a) अवतलक निकाय यद विविवालय को भंग करने क इच्छा रखता है, तो उसे राय सरकार को एतद्-

संबंधी सूचना निधाकरणत तरीके से देनी होगी। राय सरकार द्वारा यथोचित विचार के प्

त

निधाकरणत तरीके से विविवालय को विघटित कया जा सकेगा।

बशतः क विविवालय का विघटन तभी लवावी होगा जब तक क नियमित

पालम के

विवलथय का आखरी स्र अपना पालम पूरा नह कर लेता है और उन सबको डिडी
(उपाधि),

डिलोमा अथवा जिस तरह के विषय ह, लाल हो जाएँ।

(b) जैसा क तरीका निधाकरणत हो विविवालय का विघटन होने पर उसक सभी संपितयाँ
और

देनदाहरयाँ अवतलक निकाय मः निहत हगी।

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

23

(c) उप-धारा (1) के तहत राय सरकार यद विविवालय को विघटित करने का
निणय लेती है, तो

विहत तरीके से समान उेय वाली सोसाइटय मः विविवालय के विघटन

तक उप-धारा (1) के

लवधान के तहत इसके शासी निकाय क शियाँ निहत कर सकेगी।

अणुयादेश □ मण से ठकसी का उ, लंघन ठकया है और िवकुीय कु, बंधन अथवा कु, शासन क\$ िंथित

विधि विवालय मः उन्पु हो गयी है, तो वह विधि विवालय को कारण बताओ सूचना जारी कर प.तालीस ढदन के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी ढक ढय नहः एक ढशासक कः नियुक्ति कर दी जाय।

(2) विविधालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर हृदये गये उद्देश से
यहद राज्य सरकार

संतु है ढक इस अधिनयम, िनयम□, पढरिनयम□ और अ॥यादेश□ के ढकसी भी
 ००ावधान का ००थम द्दया उ०लंघन ७आ है अथवा इस अधिनयम के ढरद्वारा ढदये
 गये िनद०श□ के ००ितकूल िव०ीय कु०बंधन
 अथवा कु०शासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, िजसे वह आव०यक समझे।

(3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी ठकसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकार्य

को िनयु करेगी, जो ढकसी भी आरोप पर अपना ुतिवेदन ुंतुत करुंगे।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शिफ्टों होंगी जो

दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों को सुनवाई के दौरान दीवानी अधिनियम, 1908 में
 संविधान, 1908 में
 उद्धृत है, यथा-

(a) ठकसी ्रि□ को बुलाने और उसकऽ हाजिरी को अनवायभ्ण करने और शपथ

ठदलाकर उनकऽ जाँच करना;

(b) ्रमाण के िलए आवंयक खोज और ऐसे दंतावेज या दूसरी अउय सामग्री

्रंतुत करने का िनदश देना;

(c) ठकसी भी अदालत या कायाभ्णलय से कोई दंतावेज मंगाना।

(5) उप-धारा (3) के अंतगभ्णत िनयु□ अधिकारी या अधिकाइरय□ कऽ जाँच हरपोटभ्ण

्रार् होने के बाद यठद

राउय सरकार संतु है ठक िर्विर्वालय ने इस अधिनयम के ्रवधान के सभी

अथवा ठकसी ्रवधान का उलंघन ठकया है, िनयम□, पहरिनयम□ अथवा

अयादेश□ का उलंघन ठकया है अथवा

सरकार िनदश ्रदश िनदश□ का उलंघन ठकया है या िवह्तीय कु-्रबंधन और

कुशासन कऽ िंथित

िविर्वालय मऽ ऐसी हो गयी है ठक उसके अकादिमक ंतर पर ्रचिंन खड़ा हो गया हो, तो

सरकार एक ्रशासक िनयु□ कर सकती है।

(6) उप-धारा (5) के अंतगभ्णत िनयु□ ्रशासक इस अधिनयम के तहत बनाये गये शासी

िनकाय अथवा

्रबंधन बोडभ्ण के सारे कतभ्ण

□ का िनवभ्णहन करेगा और तब तक िर्विर्वालय कऽ गितिविधय□ का

झारखडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

संचालन करेगा जब तक िनयमित पााडम के िव्ाथय का आखरी स्रु

अपना पााडम पूरा नहल कर लेता और उअहल िडिलयौं या िडललोमा न दे दी जायँ।

(7) आखरी स्रु को िडिलयौं या िडललोमा या जैसी िंथित हो, के ँदान के बाद

ँशासक इस आशय कड ढरपोटभा राअय सरकार को देगा।

(8) उप-धारा (7) के अंतगभात ढरपोटभा ँा होने पर राअय सरकार िव्िविंालय को

िवघटत कर देगी और

िव्िविंालय के िवघटन के बाद इसकड सारी पढरसंपिडयौं और देनदाढरयौं

ँवतभाक िनकाय मल िनिहत हो जाएंगी।

अअयाअय

44. िनयम बनाने के िलए राअय सरकार कड शि

(1) इस अधिनयम के उेय के िनवभाहन के िलए शासकडय राजप् मल

अधसूचना जारी करके राअय सरकार िनयम बनाएगी।

(2) राअय िवधानमंडल के समे इस धारा के अंतगभात बनाये गये सारे िनयम को

कम से कम 30ढदन के िलए रखा जाएगा और राअय िवधानमंडल को यह

अधिकार होगा ढक वह इसका िनरसन कर दे अथवा अपेेित पढरवतभान कर दे

अथवा ऐसे पढरवतभान िजसे िवधानमंडल के उसी स्रु मल या उसके ठीक बाद

वाले स्रु मल ढकया गया हो।

45. िव्ाथय के पााडम का समापन

इस अधिनयम अथवा पढरिनयम मल ढकसी बात के होते ञए भी अंगीभूत महािविंालय अथवा िव्िविंालय कड अनुसूची मल िविनंद इस अधिनयम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अययनरत िव्ाथय या जो इस िव्िविंालय कड ढकसी

परीा मल सिमिलत होने का अधिकारी था उसे अपना पााडम पूरा करने कड अनुमित

दी जाएगी और ऐसे विवाह्य के शिर्षण, अधिशिर्षण और परीक्षा क
जिम्मेदारी संबंध विविधालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

46. कठनाई को दूर करने कऽ शि

(1) यह इस अधिनियम के कसी अधिवधान को लागू करने मऽ कठनाई उपिथत
हो रही हो तो शासकऽय राजपू मऽ अधिकांशत आदेश के द्वारा राज्य सरकार
इस अधिनियम के अधिवधान को पालन मऽ रखते शए कठनाई को शीघ्र दूर
करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

बशऽ इस अधिनियम के अधारंभ के तीन वर्ष के बाद उप धारा (1) के

अंतर्गत ऐसा कोई

आदेश पाएरत नहऽ कया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पाएरत अधेक आदेश को अवलंब राज्य
विधानमंडल के समीप रखा जाएगा।

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार, 11 अक्टूबर, 2018

अनुसूची - ए (A)

(1) एकल अधिभाव के लिए मुप पहरसर मऽ कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना
होगा और बऽ अधिभाव

के लिए 25 एकड़, जो क विविधालय कऽ स्थापना के दो वर्ष के अंदर करना
होगा। एकऽकृत क.पस मऽ अधेकागृह, कैफेटेरिया, छाावास इत्याद ऐसी सुविधायऽ
हो सकती ह., अतः जमीन कऽ आवश्यकता मऽ तदनुसार बदलाव हो सकता है।

(2) अधूनतम एक हजार वर्ग मीटर का अधिशासकऽय भवन, शैिक भवन, जिसमऽ
पुस्तकालय,

ालय कऽ,

ॐ योगशालाएँ ह॑ वह अ॒प्तम 10 हजार वर्ग॑ मीटर क॒ह॑गी, िश॑क के िलए

पया॑ आवासीय ॒

व॑ंथा,

अतिथि गृह, छा॒ावास िजसे ॒मशः इतना बढ़ाया जायेगा ॑क िव॑ा॒थय॑ क॒ह॑ कुल
सं॒या का कम से कम 25

ॐ ितशत उसम॑ रह सके, ऐसा अ॒त॒व म॑ आने के तीन वर्ष॑ के भीतर करना होगा।

अगर िव॑ि॒व॒ालय ॒

ावसा॒यिक िश॑का का काय॑म कराता है तो उसके िलए वैधा॒निक िनकाय

॒द्वारा ॑कये गये मानक॑ तथा

मानदंड॑ को ंवीकार करना होगा। रा॒ज्य सरकार ॒द्वारा िनधा॑रत मानक॑ के
आधार पर िव॑मान सं॒थान

ि॒व॒तार /पुन॑ार/पुनर॑चना करेगा।

झारखंड रा॒ज्यपाल के आदेश से,
संजय साद,
धान स॒चव-सह-४व॒ध परामश॑
४व॒ध ४वभाग, झारखंड, राँची।

वध (वधान) वभाग

अधसूचना

11 अ॒,टूबर, 2018

सं॒या-एल०जी०-22/2018-153/लेज०झारखंड ४वधान मंडल वारा यथा पा॒रत और माननीया रा॒ज्यपाल
वारा <दनांक-06/10/2018 को अनुमत राधा गो॒वि॒द िव॑ि॒व॒ालय अधिनयम, 2018का 7न०नां०कत
अं॒ेजी अनुवाद झारखंड रा॒ज्यपाल के ा॒धकार से इसके वारा काशत ०कया जाता है। िजसे भारतीय सं॒वधान
के अनु॒छेद 348 के खंड (3) के अधीन उ॒त अ॒ध॒नयम का अं॒ेजी भाषा म॑ ा॒धकृत पाठ समझा जाएगा।

THE RADHA GOVIND UNIVERSITY ACT, 2018

26

झारखंडगजट(असाधारण)गु॒+वार, 11
अ॒,टूबर, 2018 (JHARKHAND ACT, 14, 2018)

Preamble

An Act to provide for the establishment and incorporation of the **RADHA GOVIND UNIVERSITY** in the State of Jharkhand, and to confer the status of a Private University thereon and for matters connected therewith and incidental thereto;

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment and incorporation of the **RADHA GOVIND UNIVERSITY** at RAMGARH, Jharkhand promoted by RADHA GOVIND SHIKSHA SWASTHYA TRUST, RAMGARH, GOUSHALA ROAD, VIKASH NAGAR, RAMGARH (Registration No. 2555/30 dated 19.08.2013) and to confer the status of a Private University thereon and for the matters connected therewith and incidental thereto;

It is hereby enacted in the Sixty-Ninth year of the Republic of India, by the Legislature of Jharkhand, as follows:

1.Short Title, Extent and Commencement.

(1)This Act may be called "**THE RADHA GOVIND UNIVERSITY ACT, 2018**".

(2)It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

2.Definitions.

In this Act, unless the context otherwise requires:

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as specified in section 24 of the Act;

(b) "Annual Report" means the Annual report of the University as referred to in section 39 of the Act;

(c) "Board of Management" means the Board of Management of the University as constituted under section 23 of the Act;

(d) "Campus" means the area of the university in which it is established;

(e) "Chancellor" means the Chancellor of the University appointed under section 12 of the Act;

(f) "The Chief Finance and Accounts Officer" means the Chief Finance and Accounts Officer of the University appointed under section 18 of the Act;

(g) "Controller of Examinations" means the Controller of Examinations of the University appointed under section 19 of the Act;

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अक्टूबर,2018 27 (h) "Constituent College" means a college or an institution maintained by the University;

(i) "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and others staff of

(j) "Endowment fund" means the endowment fund of the University established under section 37 of the Act;

(k) "Faculty" means group of academic departments of similar disciplines;

(l) "Fee" means collection made by the university from the students for the purpose of any course of study and incidental thereto, in the University;

(m) "General Fund" means the General fund of the University established under section 38 of the Act;

(n) "Governing Body" means the Governing Body of the University constituted under section 22 of the Act;

(o) "National Assessment and Accreditation Council" means National Assessment and Accreditation Council, Bengaluru, an autonomous institution of the University Grants Commission;

(p) "Prescribed" means prescribed by the Statutes and the rules made under this Act;

(q) "Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University appointed under

section 15 of the Act;

- (r) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 17 of the Act;
- (s) "Regulatory Body" means a body established by the Government of India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Teacher Education, Medical Council of India, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, National Assessment and Accreditation Council, Indian Nursing Council, Indian Council of Agriculture Research, Council of Scientific and Industrial Research, etc. and includes the Government or any such body constituted by the Government of India or the State Government;
- (t) "Rules" means the rule of the University made under this Act;
- (u) "Schedule" means schedule appended to this Act;
- (v) "Sponsoring Body" in relation to the university means (i) a society registered under Societies Registration Act 1860, or (ii) a public trust registered under Indian Trust Act 1882, or (iii) a

28

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11

अ,दूबर,2018

society or trust registered under the law of

any other State;

- (w) "State Government" means the State Government of Jharkhand;
- (x) "Statutes", "Ordinances", and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (y) "Student of the university" means a person enrolled in the university for taking a course of study for a degree, diploma, or other academic distinction duly instituted by the university, including a research degree;
- (z) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or such of the other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College or Institution and includes the Principal of a Constituent College or institution, in conformity with the norms prescribed by the University Grants Commission;
- (aa) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants commission Act, 1956;
- (ab) "University" means the **RADHA GOVIND UNIVERSITY**, Jharkhand established under this Act.
- (ac) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 13 of the Act;
- (ad) "Visitor" means the Visitor of the University referred to in section 10 of the Act.

3. Establishment of University.

- (1) There shall be established the University by the name '**RADHA GOVIND UNIVERSITY**'
- (2) The headquarters of the University shall be within the State of Jharkhand and shall be situated at **Ramgarh**.
- (3) The University shall start operation only after the State Government issues the letter of authorization.
- (4) The university shall meet the conditions mentioned in the schedule A of the Act within the stipulated time.

(5) The Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, the Chancellor, the Vice Chancellor, the Pro Vice Chancellor, the Registrar, the Teachers, the Chief Finance and Accounts Officer and such other officers or members or authorities so long as they continue to hold such office or membership of the University hereby constitute a body corporate by the name of the University.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

(6) The University shall function as non-affiliating University and they shall not affiliate

any other college or institute for the conferment of degree, diploma and for grant of

certificate to the students admitted therein.

(7) The constituent colleges and institutions of the Sponsoring Body affiliated to and enjoying the privileges of any University immediately before the commencement of this

Act shall cease to be affiliated from that University and shall be deemed to be withdrawn from such privileges from the date of commencement of this Act and shall

be deemed to be admitted to the privileges of **RADHA GOVIND UNIVERSITY**.

University of the Sponsoring Body and all such colleges and institutions shall be the

constituent colleges and institutions of **RADHA GOVIND UNIVERSITY**.

(8) The University shall be a body corporate by the name '**RADHA GOVIND UNIVERSITY**' and will have perpetual succession and common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property, to contract and shall,

by the said name, sue or be sued.

(9) The University shall not receive any grant-in-aid or other financial assistance from the

State Government or the Central Government.

Provided that, the State Government or the Central Government may provide

financial support, including through grants or otherwise

(a) for research, development and other activities for which other State Government organizations are provided financial assistance, or

(b) for any specific research or programme based activity.

4. **Properties of the University and its Application.**

(1) On the establishment of the University the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged, or built by the University for the purpose of the

University in the State of Jharkhand shall vest in the University.

(2) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for

any purpose other than that for which the same is acquired.

(3) The properties, movable or immovable, of the university shall be administered by the

Governing Body in such manner as may be provided for by the regulations.

(4) The properties in the name of the university under sub-section (1) shall be applied for

meeting the liabilities of the university in the event of dissolution or winding up of the

university in such manner as may be prescribed in the rules.

5. Restrictions and obligations of the University.

30

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

(1) The tuition fees for professional courses such as Engineering & Technology, Medicine, Management, etc., in the university shall be determined by the University under the supervision of the regulatory body notified by the State Government from time to time.

(2) Admission in the University shall be strictly on the basis of merit. Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by the University or an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State Government.

Provided that the admission in professional educational colleges or institutions of the University shall be governed under the provisions of the Regulatory Bodies.

(3) The university shall allow merit scholarship to at least five percent of the total strength, to the students belonging to poor and economically backward classes. The relevant criteria for determining the poor and economically backward classes shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

(4) The university shall compulsorily make provisions for reservation of seats for the students domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least twenty five percent of the total students in the university. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time.

(5) The university shall make provisions for reservation of non-teaching posts in the university for the persons domiciled in the State of Jharkhand to the extent of at least fifty percent of the total number of non-teaching posts of the university. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time.

(6) The university shall appoint adequate number of teachers and officers in the University for maintaining the academic standards specified and shall ensure that the qualifications of such teachers or officers of the university shall not be lower than prescribed by the relevant Regulatory Bodies.

(7) The university shall compulsorily place in the public domain every information in relation to the University which would be of interest to the

students and other stakeholders *inter alia*, including the courses offered , number of seats under different categories, fees and other charges, facilities and amenities offered, faculty in place and such other relevant information.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

31

(8) The Convocations of the University may, for conferring degrees, diplomas or for any other purpose, be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes.

(9) The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC) within five years of its establishment and such other regulating bodies of Government of India which are connected with the courses taken up by the University and inform the State Government about the grade provided to the University. The University shall get renewed such accreditation from time to time.

(10) Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply the conditions mentioned in Schedule A of this Act, and all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies of Government of India and State Government and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

6. **Objects of the University.**

The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instructional, research and extension of facilities and in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:

(a)Innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training, and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;

(b)Studies in various disciplines;

(c)Inter disciplinary studies;

(d)National integration, secularism and social equity and International understanding and ethics.

7. **University open to all irrespective of sex, religion, class, colour, creed, or opinion.**

No person shall be discriminated against or be excluded from any office of the university or from membership of any of its authorities or from admission to any course of study leading to a degree, diploma or other academic distinction on the grounds of sex, race, creed, class, caste, place of birth and religious belief or political or other opinion.

8. **Powers and functions of the University.**

(i) To administer and manage the University, establish, administer and manage its constituent colleges and centres for research, education, training, extension and outreach including continuing education, distance learning and e-learning at its campus within the State of Jharkhand;

(ii) To provide for research, higher education, professional education, teaching training,

extension and outreach including continuing education, distance learning and e-learning in the fields of science, technology, humanities, social sciences, education, management, commerce, law, pharmacy, healthcare and any other fields;

(iii) To conduct innovative experiments in educational technologies, teaching and learning methods, to collaborate with national and international institutions and to offer joint programmes with such institutes to constantly improve the delivery of education and to achieve international standards of education;

(iv) To prescribe courses, curricula and methodologies including electronic and distance learning and provide for flexibility in the delivery of education.

(v) To hold examination and confer degree, diploma or grant certificate and other academic distinctions or title on persons subject to such condition as the University may determine and to withdraw or cancel any such degree, diploma or certificates and other academic distinction or titles in the manner prescribed by the Regulations;

(vi) to institute and award fellowships, scholarships, medals and prizes;

(vii)

to confer honorary degrees or other distinction on the manner prescribed by the Statutes;

(viii) to establish schools, centres, institutes, college and conduct the programme and courses of study as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(ix) To declare as a constituent college any college, centre, institution imparting education as are in the opinion on the University necessary for the furtherance of its objects or to establish a new constituent college, centre, institution for the purpose;

(x) To provide for printing, publication and reproduction of research, educational material and other works and to organize exhibitions, conferences, workshops and seminars; (xi) To establish knowledge resource centre;

(xii) To sponsor and undertake research and educational programmes in the fields of science, technology, humanities, social sciences, education, management, commerce, law, pharmacy, healthcare and any other allied areas;

(xiii) To collaborate or associate with any educational institution with like or similar objects; (xiv) To establish campuses including virtual campus for the purpose of achieving the objectives of the University;

(xv) To undertake research and to obtain registration in respect of such research in the nature of patents, design rights and such or similar rights with the competent authorities; (xvi) To maintain linkages and collaborate with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, through exchange of students, researchers, faculty and staff and generally in such manner as may be conducive to their common objects;

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

33

(xvii) To render services of research, training, consultancy and such other services as required for the purposes of the University;

(xviii) To develop and maintain relationships with faculty, researchers, administrators and domain experts in science, technology, humanities, social sciences, education,

- management, law, commerce, pharmacy, healthcare and allied area for achieving the objects of the University;
- (xix) to make special arrangement in respect to women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;
- (xx) To regulate the expenditure and to manage the finances and to maintain the accounts of the University;
- (xxi) To receive funds, movable and immovable properties, equipments, software and other resources from business, industry, other sections of society, national and international organization or any other source by transfers or as gifts, donations, benefactions or bequests for the purposes and objects of the University;
- (xxii) To establish, maintain and manage halls, hostels for students and quarters for the residence of faculty and staff;
- (xxiii) To construct, manage and maintain centres, complexes, auditorium, buildings, stadium for the advancement of sports, cultural, co-curricular and extra-curricular activities;
- (xxiv) To supervise and control the residence and regulate the discipline of students, faculty and staff of the University and to make arrangements for promoting their health, general welfare, social and cultural activities;
- (xxv) To fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed by the Statutes;
- (xxvi) To institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;
- (xxvii) To purchase or to take on lease or accept as gifts, bequests, legacies or otherwise any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;
- (xxviii) To sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit and consistent with the interest, activities and objects of the University;
- (xxix) To draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments;
- (xxx) To raise and borrow money on bond, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay all expenses out of the funds of the University,

34

झारखंड गजट (असाधारण) गु+वार, 11

अ. दूबर, 2018

9. Bar to affiliation.

- (1) The University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.
- (2) The University may open any off campus, offshore campus, and study centre, examination centre in or out of the State of Jharkhand only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government or State or Central Government, as the case may be.
- (3) Courses under Distance mode can be started only after the prior approval of University Grants Commission or such regulatory body established by the Government.

10. The Visitor.

- (1) The Governor of Jharkhand will be the Visitor of the University

- (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for Conferring Degrees, Diplomas, charters, Designation and certificates.
- (3) The Visitor shall have the right to visit the University or any institution maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the university.

11. **Officers of the University.**

The following shall be the officers of the University:

- (a) The Chancellor
- (b) The Vice Chancellor
- (c) The Pro Vice Chancellor
- (d) Director/Principal
- (e) The Registrar
- (f) The Chief Finance and Accounts Officer
- (g) The Controller of Examinations
- (h) The Dean of Students Welfare
- (i) The Dean of Faculty
- (j) The Proctor, and
- (k) Such other officers as may be declared by the Statute to the officers of the University.

12. **The Chancellor:**

- (1) The Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of five years with the approval of the Visitor by following such procedures and on such terms and conditions as may be prescribed. On the expiry of the term, the Chancellor may be reappointed by the Sponsoring Body in consultation with the Visitor.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

35

- (2) The Chancellor by virtue of his office shall be the head of the University.
- (3) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the University for conferring degrees, diplomas, or other academic distinctions.
- (4) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the head of the sponsoring body resign his office.
- (5) The Chancellor shall have the following powers, namely:
 - (a) to call for any information or record;
 - (b) to appoint the Vice Chancellor;
 - (c) to remove the Vice Chancellor in accordance with the provisions of this Act; and
 - (d) such other powers as may be conferred on him by this Act or Statutes made thereunder.

13. **The Vice Chancellor:**

- (1) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the qualifications

prescribed by the University Grants Commission and shall hold office for a period of five years .Provided that a person appointed as Vice Chancellor shall retire from office during tenure of his office or extension thereof, if any when he completes the age of 70 years.

Provided further that after the expiry of the term of five years, the Vice Chancellor shall be eligible for re-appointment for another term of five years.

- (2) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the university and shall execute the decisions of various authorities of the university.
 - (3) In the absence of both the Visitor and the Chancellor, the Vice Chancellor shall preside over the convocation of the university.
 - (4) The Vice Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters;
- Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

sub section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of

communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice Chancellor.

- (5) The Vice Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

14. Removal of the Vice Chancellor.

- (1) If at any time and after such inquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice Chancellor:
 - (a) has failed to discharge any duty imposed upon him by or under this Act, the Statutes, the Ordinances, or
 - (b) has acted in a manner prejudicial to the interests of the university, or
 - (c) is incapable of managing the affairs of the university, then the Chancellor may,

notwithstanding the fact that the term of office of the Vice Chancellor has not

expired, require the Vice Chancellor, by an order in writing stating the reason

therefore, to resign his post from the date as may be specified in the order.

- (2) No orders under sub –section (1) shall be passed unless a notice stating the specific

grounds on which such action is proposed , has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice Chancellor.

15. The Pro Vice-Chancellor:

- (1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall

exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

- (2) The Pro Vice-Chancellor appointed under sub section (1) shall discharge his duties in

addition to his duties as a Professor.

- (3) The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice Chancellor in discharging his duties as

and when required by the Vice Chancellor.

- (4) The Pro Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by

the sponsoring body.

16. Director(s)/Principal(s):

The Director/Principal shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and

perform such functions as may be prescribed.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

37

17. Registrar:

- (1) The Registrar shall be appointed by the Chairperson of the Sponsoring Body in such manner, as may be specified in the Statutes. The Registrar shall possess the qualifications prescribed by the University Grants Commission.

- (2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other power and perform such other functions as may be prescribed.

- (3) The Registrar shall be the ex officio Member Secretary of the Executive Council and the Academic Council but shall not have a right to vote.

18. The Chief Finance and Accounts Officer:

- (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chairperson of the Sponsoring Body in such manner as may be specified by the Statutes.

- (2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the Statutes.

19. The Controller of Examinations:

- (1) The Controller of Examinations shall be whole time officer of the university and shall be appointed by the Chancellor in accordance with the Statutes.
- (2) it shall be the duty of the Controller of Examinations:
 - (a) to conduct examinations in a disciplined and efficient manner;
 - (b) to arrange for the setting of question papers with strict regards to secrecy;
 - (c) to arrange for the evaluation of answer sheets in accordance with the planned time schedule for results;
 - (d) to constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students;
 - (e) to deal with any other matter connected with examinations which may, from time to time be assigned to him by the Vice Chancellor.

20. Other Officers: Manner of appointment and power and duties of the other officers of the University including the Dean of Students Welfare, Dean of faculty, and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

21. Authorities of the University:

The following shall be the authorities of the University:

- (a) The Governing Body
- (b) The Board of Management
- (c) The Academic Council
- (d) The Finance Committee
- (e) The Planning Board
- (f) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

22. The Governing Body:

- (1) The Governing Body shall have the following members, namely:
 - (a) the Chancellor;
 - (b) the Vice-Chancellor;
 - (c) the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or his nominee;
 - (d) five persons nominated by the sponsoring body, out of which two shall be eminent educationists;
 - (e) one expert of management or technology from outside the university, nominated by the Chancellor; and
 - (f) one expert of finance, nominated by the Chancellor.
- (2) The Governing Body shall be the supreme authority and principal governing body of the University. It shall have the following powers, namely:
 - (a) to provide general superintendence and directions and to control the functioning

of the university by using all such powers as are provided by this Act, Statutes,

Ordinances, Regulations or Rules;

(b) to review the decisions of other authorities of the university in case they are not

in conformity with the provisions of Act, Statutes, Ordinances, Regulations or

Rules;

(c) to approve the budget and annual report of the university;

(d) to lay down the extensive policies to be followed by the university;

झारखण्डगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

39

(e) to recommend to the sponsoring body for the dissolution of the university if

a situation arises when there is no smooth best efforts; and

functioning of the university in spite of

(f) such other powers as may be specified by the Statutes.

(3) The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year.

(4) The quorum of the meeting shall be four;

Provided that the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, or in his absence, Director, Higher Education shall be present in each meeting in which decisions on issues involving Government policies/ instructions are to be taken.

23. The Board of Management.

(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical

Education, Jharkhand or his nominee;

(c) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(d) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(e) three persons, from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body;

(f) two teachers, nominated by the Vice Chancellor.

(2) The Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the Statutes.

(4) The quorum for the meeting of the Board of Management shall be five;

Provided that the Secretary to the Government, Department of Higher and

Technical Education, Jharkhand, or in his absence, Director, Higher Education shall be present in each meeting in which decisions on issues involving Government policies/ instructions are to be taken.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

24. The Academic Council.

- (1) The Academic Council shall consist of the Vice Chancellor and such members as may be specified by the Statutes.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.
- (3) The Academic Council shall be the principal academic body of the university and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or Rules, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the university.
- (4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the Statutes.

25. The Finance Committee.

- (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.
- (2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed

26. The Planning Board.

- (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University and shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils.
- (2) The constitution of the planning board, term of office of its members and its power and functions shall be such as may be prescribed.

27. Other Authorities.

The constitution, powers and functions of other authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

28. Disqualification for membership of an authority or body.

A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities or bodies of the university, if he/she:

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude;
- (d) has been punished for indulging or in promoting unfair practice in the conduct of any

examination , in any form, anywhere.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

41

29. Vacancies not to invalidate the constitution of, or the proceedings of any authority or body of university.

No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy in or defect in the constitution of any authority or body of the University.

30. Constitution of Committees.

The authorities of the University may constitute such committee with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed shall be such as may be prescribed by the Statutes.

STATUTES, ORDINANCE AND REGULATIONS

31. First Statute.

(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First Statutes may

provide for all or any of the following matters, namely:

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as maybe constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Chancellor, the Vice Chancellor and their powers and functions;
- (c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer, their powers and functions;
- (d) the manner and terms and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;
- (e) the terms and conditions of service of employees of the University;
- (f) the procedure for arbitration in cases of disputes between employees or students and the University;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the provisions regarding exemption from payment of tuition fee and awarding scholarships and fellowships to the students;
- (i) framing of policy for admission, including regulation of reservation of seats; and
- (j) fees to be charged from students.

- (2) The First Statutes of the University shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the State Government for its approval.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

- (3) The State Government shall consider the First Statutes, submitted by the University and shall approve it within sixty days from the date of its receipt, with or without modifications as it may deem necessary.
- (4) The University shall communicate its agreement to the First Statutes as approved by the State Government, and if it desires not to give effect to any or all the modifications made by the State Government under sub-section (3), it may give reasons therefore and after considering such reason, the State Government may or may not accept the suggestions made by the University.
- (5) The State Government shall publish the First Statutes, as finally approved by it, in the publication.

32. Subsequent Statutes.

- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereafter, the subsequent Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely :-
- (a) Creation of new authorities of the University;
 - (b) Accounting policy and financial procedure;
 - (c) Representation of teachers in the authorities of the University;
 - (d) Creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;
 - (e) Institution of medals and prizes;
 - (f) Procedure for creation and abolition of posts;
 - (g) Revision of fees;
 - (h) Alteration of the number of seats in different disciplines; and
 - (i) All other matters which by or under the provision of this Act required to be prescribed by the Statutes.
- (2) The Statutes of the University other than the First Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.
- (3) The Statutes made under sub-section (2) shall be submitted to the State Government and it may approve or, if considers necessary, give suggestions for modification as far as possible within two months from the date of receipt of the Statutes.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018 43 (4)

The

Government.

(5) The State Government shall consider the comments of the Governing Body and may approve the Statutes with or without modifications and it shall be published by it in the Official Gazette, and shall come into force from the date of such publication.

33. First Ordinance.

(1) Subject to the provisions of this Act, the rules and the Statutes made thereunder, the First Ordinances may provide for all or any of the following matter, namely :-

- (a) The admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) The courses of study to be laid down for degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) The award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same;
- (d) The conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) The conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies examiners and moderators;
- (f) Fees to be charged for the various courses examinations, degrees or diplomas of the University;
- (g) The conditions of residence of the students of the University;
- (h) Provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) The creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
- (j) The manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education;
- (k) Such other matters which are required to be provided by the Ordinances by or under this Act.

(2) The First Ordinances of University shall be made by the Chancellor which after being approved by the Board of Management, shall be submitted to the State Government for its approval.

44

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

(3) The State Government shall consider the First Ordinance submitted by the Chancellor under sub-section (2) within sixty days from the date of its receipt and may approve it or give suggestions for modifications therein.

(4) The Chancellor shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the First Ordinances along with such reasons, if any, to the State Government and on receipt of the same, it shall consider the comments of the Chancellor and may approve the First Ordinances of the University with or without such modifications and it shall be published by the State Government in the Official Gazette, and it shall come into force from the date of such publication.

34. Subsequent Ordinances.

- (1) All Ordinances other than the First Ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Governing Body shall be submitted to the State Government for its approval.
- (2) The State Government shall consider the Ordinances submitted by the Academic Council under sub-section (1) as far as possible within two months from the date of its receipt and may approve it or give suggestions for modifications therein.
- (3) The Academic Council shall either modify the Ordinances incorporation the suggestion of the State Government or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the State Government and shall return the Ordinances along with reason, if any, to the State Government and on receipt of the same, it shall consider the comments of the Academic Council and may approve the Ordinances with or without modifications and it shall be published by it in the Official Gazette, and shall come into force from the date of such publication.

35. Regulations.

The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Governing Body make Regulation, consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of business of the each such authority and committee constituted by each such authority.

36. Powers of State Government to give directions.

- (1) The State Government may, for the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

45

- (2) The State Government shall communicate its recommendations to the University on the basis of such assessment for corrective action. The University may adopt such corrective measures and make efforts so as to ensure the compliance of the recommendations.
- (3) The State Government may give such directions as it may deem fit if the University fails to comply with the recommendation made under sub-section(2) within a reasonable time. The directions given by the State Government shall be immediately complied by the University.

FUNDS OF UNIVERSITY

37. Endowment Fund.

- (1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the university with an amount specified in the Letter of Intent.
- (2) The Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure that the university complies with the provisions of this Act and functions as per the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances. The State Government shall have the power to forfeit, a part or whole of the Endowment Fund in case the university or the sponsoring body contravenes the provisions of this Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the rules made there under.

- (3) The university may utilize the income from the Endowment Fund for the development of infrastructure of the university and not to meet the recurring expenditure of the university.
- (4) The amount of Endowment Fund shall be invested in such instruments as the Government may prescribe and kept invested until the dissolution of the university.
- (5) In case of investment in long term security, the certificates of the securities shall be kept in the safe custody of the Government and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit account in the Government Treasury, deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn without the permission of the Government.

38. General Fund.

(1) The university shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which the following shall be credited, namely:

- (a) Fees and other charges received by the university;
- (b) Any contribution made by the sponsoring body;

46

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,टूबर,2018

- (c) Any income received from consultancy and other work undertaken by the university in pursuance of its objective;
- (d) Trusts, bequests, donations, endowments and any other grants; and
- (e) All other sums received by the university.

(2) The General Fund shall be utilized for the following objects, namely:

- (a) For the repayment of debts including interest charges thereto incurred by the university for the purposes of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations, and the Rules made there under with the prior approval of the Governing Body;

(b)

To upkeep the assets of the university; (c) For the payment of the fee for audit of the funds created under sections 37 and 38;

- (d) To meet with the expenses of any suit or proceedings by or against the university;

(e)

For the payment of salaries, allowances, provident fund contributions, gratuity and other benefits to officers, employees, and members of the teaching and research staff;

- (f) For the payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council, other authorities and the members of any committee appointed by any of the authority or the Chairperson of the sponsoring body or the Chancellor;

(g) For the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to economically weaker sections of the society or research associates, trainees or, as the case may be, in any student otherwise eligible for such awards under the Statutes, the Ordinances, the Regulations or the Rules;

- (h) For the payment of any expenses incurred by the university in carrying out the provisions of Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the Rules;

(i) for the payment of cost of capital, not exceeding the prime lending rate

from time to time of the State Bank of India, incurred by the sponsoring body for setting up the university and the investments made therefore;

(j) for the payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the university in pursuance of this Act, Statutes, the Ordinances, the regulations or the rules;

(k) for the payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the university, on behalf of the sponsoring body, as approved by the Governing Body to be an expense for the purposes of the university;

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

47

Provided that no expenditure shall be incurred by the university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Governing Body, without prior approval of the Governing Body.

ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

39. Annual Report.

The Annual Report of the University shall be prepared by the University which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be submitted to the State Government.

40. Audit and Annual Accounts.

(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared by the University and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the State Government.

WINDING UP OF UNIVERSITY

41. Winding up of University.

(1) If the sponsoring body proposes to dissolve itself according to the provisions of law governing its constitution or incorporation; it shall give at least six months prior notice to the State Government.

(2) The State Government shall, on receipt of such notice make such arrangements as may be necessary, for the administration of the University from the date of dissolution of the sponsoring body till the completion of syllabus by the last batch of students admitted to the University and may also cause the functioning of the University to continue by appointing an administrator in place of the sponsoring body, who shall be entrusted with the powers, duties and functions of the Sponsoring body, duties and functions of the Sponsoring Body as prescribed under this Act.

42. Dissolution of University.

(1) The Sponsoring Body who intends to dissolve the University shall give a notice to that effect in the prescribed manner to the State Government. The State Government, after due consideration, may dissolve the University in the manner as may be prescribed;

Provided that the dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or, as the case may be, awards.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Sponsoring Body in the manner as may be prescribed.

(3) Where the State Government decides under sub-section (1) to dissolve the University, it may vest the powers of the Governing Body in the prescribed manner to other societies having similar objects till the dissolution of the University takes effect under the proviso to sub-section (1).

43. Special powers of State Government under certain circumstances.

(1) Where the State Government is of the opinion that the University has contravened any of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or has violated any of the direction issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue the notice requiring the University to show cause within forty-five days as to why an administrator be not appointed.

(2) On receipt of reply of the University on the notice issued under sub section (1), if the State Government is satisfied that there is a prima facie case of contravention of any of the provision of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made thereunder or violation of directions issued by it under this Act or there is financial mismanagement or maladministration, it shall make an order of such inquiry as it may consider necessary.

(3) The State Government shall, for the purposes of any such inquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely :-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b)

Requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) Requisitioning any public record from any court or office.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अ,दूबर,2018

49

(5) On receipt of the inquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the State Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes or the Ordinances made there under or has violated any of the directions issued by it under this Act or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it may appoint an administrator.

(6) The administrator appointed under sub-section (5) shall exercise all the powers and perform all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University

until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded with degrees, diplomas or, as the case may be, awards.

(7) After having been awarded the degrees, diplomas or, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to that effect to the State Government.

(8) On receipt of the report under sub-section (7), the State Government shall dissolve the University and on dissolution of the University, all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body.

MISCELLANEOUS

44. Power of the State Government to make Rules.

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the State Legislature as soon as may be after they are made and shall be subject to rescission by the State Legislature or to such modification as the State Legislature or to such modification as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.

45. Completion of courses of students.

Notwithstanding anything contained in this Act or the Regulations, any student of the constituent colleges or institutions of the University specified in the Schedule and affiliated to any University who immediately before the commencement of this Act was studying or was eligible for any examination of that University shall be permitted to complete his course in preparation therefore, and the University shall provide for the instruction, teaching, training and examination of such students, in accordance with the courses of studies of the respective University in such manner and for such period as may be prescribed.

झारखंडगजट(असाधारण)गु+वार,11 अक्टूबर,2018

46. Power to remove difficulties.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no notification order under sub section (1) shall be made after the

expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

SCHEDULE A

(1) Acquire not less than 10 acres of land for its main Campus, if single-domain, and 25 acres of land, if multi-domain within two years after starting the functioning of the university. An integrated campus may have certain facilities in common such as auditorium, cafeteria, hostels, etc. and hence the land requirement may vary accordingly.

(2) Construct administrative building of at least 1000 sq. mtrs., academic building including library, lecture theatres, laboratories of at least 10000 sq. mtrs., adequate residential accommodations for teachers, guest houses, hostels which shall gradually be increased to accommodate at least 25% of the total student strength in each course within 3 years of its coming into existence. In case the University is conducting professional programmes of study, prevailing norms and standards of respective statutory body shall be applicable. Existing institutes must undertake expansion/renovation/restructuring to meet the prescribed norms of the State Government.

***** **

झारखंड रा;यपाल के आदेश से,

संजय साद,

धान स3चव-सह-4व3ध परामशY
4व3ध 4वभाग, झारखंड, राँची।

झारखंड राजरखड राजक@य मुbणालय क@य मुbणालय, राँची वारा काशत एवं मु<त
झारखंड गजट (असाधारणअसाधारण) 974 -- 50